भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.02.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 294 का उत्तर

मानवरहित रेल समपार

294. श्री महेश साहूः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री मनोज तिवारीः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मानवरहित रेल समपारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन मानवरहित रेल समपारों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें अगले पांच वर्षों में मानवरहित समपारों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार देश के विभिन्न रेल समपारों पर, विशेषकर दिल्ली/एनसीआर, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंडरपास और ओवरब्रिज के निर्माण पर विचार कर रही है ताकि वाहन यातायात भीड़ को कम किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निर्माणों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन निर्माणों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): भारतीय रेल के बड़ी आमान मार्गों पर कोई भी मानवरहित समपार (यूएमएलसी) नहीं है। बहरहाल, 01.04.2020 को, मीटर आमान (एमजी) और छोटी आमान (एनजी) पर कुल

948 यूएमएलसी मौजूद हैं, जिन्हें भविष्य में आमान परिवर्तन कार्यों के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। यूएमएलसी की राज्य-वार सूची संलग्न है।

(ग) और (घ): 01.04.2020 को, रेलवे ने दिल्ली/एनसीआर, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में 1566 ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) और 6219 अंडरपास/निचले सड़क पुल (आरयूबी) स्वीकृत किए हैं। सरकार विभिन्न समपारों पर अंडरपास और ऊपरी पुलों के निर्माण पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। बहरहाल, आरओबी/आरयूबी का निर्माण कार्य समपार समाप्त करने के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करके और लागत भागीदारी वहन करके, जहां भी लागू हो, पहुंच मार्गों के लिए अधिक्रमण मुक्त भूमि, तकनीकी व्यवहार्यता, जनोपयोगी सुविधाओं का अंतरण, राज्य एजेंसियों द्वारा पर्याप्त निधियों का आबंटन, जन सहयोग आदि पर निर्भर करता है। अत:, आरओबी/आरयूबी को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ड.): रेलवे ने आरओबी/आरयूबी/सबवे की निर्माण प्रगति को बेहतर करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके अग्रसक्रिय उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- संरेखण और सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त सर्वेक्षण।
- विभिन्न स्पैन के लिए डिज़ाइन एवं ड्राइंग का मानकीकरण।
- राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें।
- एकल इकाई आधार पर आरओबी का निर्माण।
- विभिन्न स्तरों पर प्रगति की निगरानी।

******

मानवरहित रेल समपार के संबंध में दिनांक 03.02.2021 को लोकसभा में श्री महेश साहू, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री मनोज तिवारी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री सुधीर गुप्ता के अतारांकित प्रश्न सं. 294 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

(क) और (ख): 01.04.2020 को राज्य-वार मानवरहित समपार:-

क्र.सं.	राज्य	मीटर लाइन	छोटी लाइन	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	असम	0	0	0
3	बिहार	0	0	0
4	चंडीगढ़	0	0	0
5	छतीसगढ़	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	0
7	गोवा	0	0	0
8	गुजरात	160	169	329
9	हरियाणा	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	4	4
11	जम्मू कश्मीर	0	0	0
12	झारखंड	0	0	0
13	कर्नाटक	0	0	0
14	केरल	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	137	137
16	महाराष्ट्र	0	109	109
17	मणिपुर	0	0	0

18	मिज़ोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0
21	पुदुचेरी	0	0	0
22	पंजाब	0	0	0
23	राजस्थान	97	52	149
24	तमिलनाडु	0	0	0
25	तेलंगाना	0	0	0
26	त्रिपुरा	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	51	2	53
28	उत्तराखंड	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	167	167
	कुल	308	640	948

******